the patients to the Cancer Hospital proper where it could be done. The implication here is, if I may be frank about it, that some doctors felt that if they came to the hospital, they could get fee while if they went to the other hospital, they got it free. This is the controversy involved.

SHRI JYOTIRMOY BASU : It is not right at all. On the contrary, it is just the other way round.

SHRI NATH PAI : You will agree, Sir, that very often prevention is better than cure and I would like to ask my question based on this. Is the Government by way of its campaign against spread of cancer trying to draw the attention of a large number of fellow Indians that continuing chewing of pan is likely to lead to cancer of the mouth.

Secondly, are the producers or manufacturers of tobacco under any obligation as in advanced countries to advertise that the chewing or smoking of tobacco is a health hazard ? Is there a law to oblige the manufacturers; if not, is the Government thinking of having any such law ?

May I repeat, Sir, that in advanced countries no longer cigarettes can be advertised without at the same time pointing out that smoking of cigarettes is a serious health hazard. Will that thing be required in India ?

DR. S. CHANDRASEKHAR : I agree with the hon. Member that in the United States of America, UK and other European countries the modern package of cigarette pack carries a warning: 'You are smoking at the risk of your health. Smoking is a health hazard'. In all the TV advertisements, that has to be repeated, and in spite of that people say 'I have got a habit' and so the incidence is then. The hon. Member's suggestion is an excellent idea. We may explore in the Ministry whether we may have also some legislation like that to discourage people from smoking. As one who does not smoke cigarettes, I agree with the hon. Member.

As for chewing, several hon. Members chew. The Madras Cancer centre has done a lot of research in the last 10 years. They have found chewing pan and not only that, storing it in the cheek has been a very potent factor in oral dancer.

SHRI NATH PAI: Sir, would you use your great authority to dissuade members from chewing pan in the interests of their health ?

SHRI G. VISWANATHAN : I want to know whether the Minister is aware that the Arignar Anna Institute of Cancer has been started in Kancheepuram. May I know whether they have asked for any financial assistance and whether the Government would extend them all financial and other assistance ?

DR. S. CHANDRASEKHAR : The Cancer institute is started in memory of the late Chief Minister of Madras Shri C. N. Annadurai, and they have made an application to get some support from us, we are examining it and I think it will be finalised at an early stage.

SHRI R. K. BIRLA: May I know from the Government whether the Government is thinking of waiving out the capital punishment, that is, hang to death, to the criminals who offer their bodies for experiment of research by getting the cancer germs generatted in their bodies as in the case of the USA where on account of this, there has been early detection and early cure of this nasty disease ?

DR. S. CHANDRASEKHAR : The Kettering Institute in New York has got sophisticated equipments and highly trained personnel to do that kind of research which we do not have here and hence his suggestion is rather out of place for us.

मुद्रा परिचालन

†

*1532. श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री राम स्वरूप विद्यार्थी :
श्री वंश नारायण सिंह :
श्री राम सिंह अयरवाल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में सरकार द्वारा कितने मूल्य के नये नोट छापे गये; और

(ख) गत तीन वर्षों में कुल कितनी मुद्रा प्रचलन में थी ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI P.C. SETHI): (a) and (b). A statement is laid on the Table of the House.

Statement

The value of currency and bank notes printed by the Currency Note Press, Nasik Road, and supplied to the Reserve Bank of India during the last three years is as follows :

	(In crores of rupees)
1967-68	2,181·17
1968-69	2,311·07
1969-70	2,390·54

The total money supply with the public as on the last Friday of the three financial years was as follows :

	(In crores of rupees)
1967-68	5,350
1968-69	5,779
1969-70	6,349

Of this, total currency in circulation with the public as under:

	(In crores of rupees)
1967-68	3,376
1968-69	3,682
1969-70	4,006

श्री कंवर लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, स्टेटमेन्ट से यह बात स्पष्ट है कि रुपये की सप्लाई हर साल बढ़ रही है, पिछले साल 570 करोड़ रुपया बढ़ा । इस का परिणाम यह होता है कि प्राइस इन्क्रीज होती है, कास्ट आफ़ लिविंग ज्यादा हो जाता है । रिजर्व बैंक को इस के बारे में पूरा अधिकार है । मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं—रिजर्व बैंक ने आज तक यह नहीं बताया कि कास्ट आफ़ लिविंग और प्राइस इन्क्रीज का मनी-सप्लाई से क्या बेसिज़ है, उन का रिलेशन क्या है ? क्या सरकार एक हाई-पावर्ड कमीशन बैठायेगी जो इस के बारे में मालूम करे और सरकार को बतालाये कि इन दोनों चीजों का बेसिज़ क्या होना चाहिये, ताकि रुपये की सप्लाई ठीक तरह से हो और जिस से कीमतें न बढ़ें, कास्ट आफ़ लिविंग न बढ़े ?

दूसरा सवाल—क्या सरकार बड़े-बड़े नोटों को वापस लेने के बारे में, डीमोनिटाइजेशन के बारे में नहीं सोच रही है ? कई बार ऐसी रियूमर्ज उठती हैं—सरकार इस के बारे में स्पष्टीकरण करे ?

SHRI P. C. SETHI : In broad terms it would be said that in so far as money supply increases at more or less the same rate at which the national output expands it does not lead to inflationary pressures. So far as demonetisation is concerned, Government has made it amply clear many times before that demonetisation is not a solution to the problem.

श्री कंवर लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, मैंने हाई-पावर्ड कमीशन के बारे में पूछा था । मैंने पूछा था—मनी सप्लाई और कौस्ट आफ़ लिविंग तथा प्राइस इन्क्रीज़ का क्या रिलेशन है ? इस का बेसिज़ मालूम करने के लिये सरकार कोई हाई-पावर्ड कमीशन बैठायेगी ?

श्री प्र० चं० सेठी : अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा थ —अगर मनी सप्लाई बढ़ती है तथा उसी मात्रा में अगर चीजों का उत्पादन बढ़ जाय तो उस का इन्फ्लेशनरी-प्रेशर हो, यह जरूरी नहीं है। इस के कई कारण हैं, जिनमें से एक कारण यह भी है कि अगर यह प्रोडक्शन के साथ-साथ चलता है, तो उस मनी-प्रेशर से कीमतें बढ़ने का अन्देशा नहीं होता है ।

श्री कंवर लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, क्या इन्होंने मेरे प्रश्न का जवाब दे दिया । मैंने हाई-पावर्ड कमीशन के बारे में भी पूछा था ?

SHRI P. C. SETHI : It is not considered necessary.

श्री कंवर लाल गुप्त : अभी माननीय मंत्री महोदय ने कहा जिस हिसाब से प्रोडेक्शन बढ़ता है, अगर उसी हिसाब से मनी सप्लाई भी बढ़े तो इन्वेस्टमेन्ट ज्यादा होगा, रेट-आफ़-इन्टरेस्ट कम होगा और जब इन्वेस्ट-मेन्ट ज्यादा होगा तो प्रोडेक्शन ज्यादा बढ़ेगा और उससे कीमतें गिरनी चाहियें, बशर्ते कि हमारी इकानमी प्रोपरली मैनेज्ड हो। लेकिन अनमैनेज्ड होने की वजह से कीमतें बढ़ती जा रही हैं, बैंक नेशनलाइजेशन के बाद तो रिज़र्व बैंक की अन-फैटर्ड पावर्ज हो गई हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी वे ही तय करते हैं और मनी सप्लाई भी वे ही करते हैं। क्या सरकार इन दोनों कामों को —क्रेडिट और इन्टरेस्ट का मामला तथा सलाई आफ़ मनी—इन दोनों को अलग अलग करेगी ? क्या सरकार कोई इण्डीपेन्डेन्ट मौनिटरी, अथोरिटी कायम करेगी, जो पौलिटीकल कन्सीड्रेशन्ज से परे हो ? जैसे जूडीशियरी एक्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर—तीन इण्डी-पेन्डेन्ट अथारिटीज़ होती है, उसी प्रकार एक फोर्थ-पिलर, जो डेमोक्रेटिक सैटअप के लिये जरूरी है, इन्डीपेन्डेन्ट मौनिटरी अथोरिटी सरकार कायम करे, जिससे मनी की सप्लाई पोलिटीकल कन्सीड्रेशन्ज से परे, ठीक प्रकार से हो सके?

श्री प्र० चं० सेठी : अध्यक्ष महोदय, जहां तक रिजर्व बैंक के कार्य करने का ताल्लुक है, यह कहना कि वह किसी पोलिटीकल कन्सीड्रेशन, राजनीतिक दबाव या इशारों से काम करता है, उचित नहीं है। वह एक इण्डीपेन्डेंट ओटोनामस बाडी है, जो इन चीज़ों को रेग्यूलेट करता है।

माननीय सदस्य ने कहा कि मनी सप्लाई से भाव बढ़ता है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा—जहां तक दूसरे और तीसरे प्लान पीरियड का ताल्लुक है—मनी सप्लाई 29.4 और 57.9 बढ़ी, लेकिन इस के मुकाबले में जहां तक कीमतों का ताल्लुक है—35 परसेन्ट और 32.5 परसेन्ट कीमतें ही बढ़ीं। इस लिए जैसा मैंने इशारा किया था, अगर मनी सप्लाई के साथ-साथ प्रोडक्शन कन्ज्यूमर गुड्स की बढ़ती है तो लाज़मी नहीं कि मनी सप्लाई के साथ-साथ भाव भी बढ़ें।

जहां तक रिजर्व बैंक का ताल्लुक है—हर क्रेडिट के बीच में वह नहीं आता है, जहां पांच लाख रुपए से ऊपर का क्रैडिट तय करना हो, ऐसे केसेज़ को देखने का रिज़र्व बैंक को अधिकार है, बाकी मामलों में स्टेट बैंक दूसरे बैंक्स और उनकी सबसीडियरीज़ अपने आप क्रेडिट तय करते हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त : इण्डीपेन्डेन्ट मोनिटरी अथोरिटी के बारे में कुछ नहीं कहा।

श्री प्र० चं० सेठी : रिजर्व बैंक स्वयं एक इण्डीपेन्डेन्ट आटोनोमस बाडी है।

श्री रामस्वरूप विद्यार्थी : मैं जानना चाहता हूं कि 10 हजार, 5 हजार और एक हजार रुपए की डिनोमिनेशन के कितने नोट्स हैं ? उनमें से कितने पब्लिक सर्कुलेशन में हैं और कितने ऐसे नोट्स हैं जो रूस और अमरीका के हाथों में हैं ? यदि हैं, तो कौन-कौन से बैंकों में हैं ?

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक 1 हजार रुपए के डिनोमिनेशन के नोटों का ताल्लुक है—1969-70 में 2 लाख 52 हजार 1 सौ थे। जहां तक 5 हजार रुपए के डिनो-मिनेशन के नोटों का ताल्लुक है—1969-70 में 48,400 थे, जहां तक 10 हजार रुपए के डिनोमिनेशन का ताल्लुक है—1969-70 में 30 हजार थे। अमरीका के पी० एल० 480 फण्ड्स का जहां तक ताल्लुक है—60 करोड़ रुपया अमरीकन बैंक्स में है, बाकी रुपया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में है, इस लिए कितना सर्कुलेशन में है यह नहीं कहा जा सकता।

श्री राम स्वरूप विद्यार्थी : अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा था कि 10 हजार, 5 हजार और 1 हजार डिनोमिनेशन के कितने नोट्स हैं, उनमें से पब्लिक सर्कुलेशन में कितने हैं ? दूसरी बात मैंने यह पूछी थी कि अमरीका और रूस के खातों में कितने नोट्स हैं और किस-किस बैंक में हैं ? मेरे इन स्पेसिफिक प्रश्नों का जवाब दिया जाए ।

श्री प्र० च० सेठी : जहां तक पब्लिक सर्कुलेशन और मनी सप्लाई का ताल्लुक है, मैंने मूल सवाल के उत्तर में बताया है कि 1969-70 में 6349 करोड़ रुपए की टोटल मनी सप्लाई थी, जब कि करेन्सी-इन-सर्कुलेशन 4006 करोड़ रुपए थी। मनी सप्लाई और करेन्सी सर्कुलेशन में फर्क यह है कि करेन्सी सर्कुलेशन के अलावा, जो करेन्ट डिपाजिट्स और सेविंग्ज़ डिपाजिट्स होते हैं, उनको जोड़ कर मनी-सप्लाई मानी जाती है, लेकिन इन डिनोमिनेशन्ज़ के कितने नोट्स डिपाजिट में है, इसका ब्रेक-अप इस समय मेरे पास नहीं है ।

श्री महाराज सिंह भारती : मंत्री महोदय, ने अभी बतलाया—अगर देश में उत्पादन बढ़ जाए और करेन्सी भी दढ़ जाए, तो मंहगाई नहीं आती । क्या रिज़र्व बैंक ने कोई ऐसा फार्मूला बनाया है, जिसके ज़रिये यह जाना जा सकता हो कि कितना उत्पादन बढ़ने पर कितनी करेन्सी बढ़ाई जा सकती है ।

SHRI P. C. SETHI: There is no formula according to which this is being done. But if the money supply increases and the consumer goods production also increases the resultant effect on inflation would not be much.

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: Is it a fact that some Naga hostiles and Kanu Sanyal, the Naxalite leader, have just returned from China and they have carried fake Indian currency worth about Rs. 5 lakhs? Have Government inquired into this and taken suitable action to see that no unfavourable or adverse effect is produced in our country on account of the circulation of this fake currency ?

SHRI P. C. SETHI : In reply to question No. 155 on 2nd March 1970, I had said that so far there is no evidence to support the allegation about such smuggling of currency into Indian territory. A CBI inquiry had been ordered and they have said there is no evidence on this point.

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: Two months have passed since that reply was given. Kanu Sanyal has been active in Assam with the Naga hostiles. This was the report of last week. Instead of relying on past information, will Government take the latest news into consideration?

SHRI P. C. SETHI: I made the statement on the basis of past information. If the hon. member has any specific information, she may supply it to us.

MR. SPEAKER: She should have put a specific question on this.

SHRI J. H. PATEL: In his statement, the hon. member has given the amount of currency in circulation today. Out of the total circulation, how much of it is official and how much counterfeit ? The existence of counterfeit has been admitted. It is not only internal production but some foreign agencies are also at it. Has the Reserve Bank been able to find out the exact amount of counterfeit currency in circulation in the country ?

SHRI P. C. SETHI: The figures I have given are of the currency in circulation officially. As far as counterfeit currency is concerned, I have said that with regard to China there is no evidence of their having printed and smuggled Indian notes here. As for smuggling of counterfeit notes from Pakistan, on the Indo-Pakistan border, last year and the year before currency notes of 100 rupees denomination were caught hold of. But their number was 29 and 22.

As regards the other part, about fake currency inside the country, the police and the central department concerned are quite vigilant and wherever it is found, it is checked.

श्री शशि भूषण : अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान में सूदखोरों, आढ़तियों और ब्लैकमार्केटियर्स के पास ब्लैक का लगभग चार हजार करोड़

रुपया है जिसकी वजह से हमारी मुद्रा के चलन में, उसके संतुलन में दिक्कत आती है, मैं जानना चाहता हूं कि उसको रोकने के लिए सरकार तथा कार्यवाही कर रही है जिससे कि हमारी मुद्रा आसानी से चल सके ?

SHRI P. C. SETHI : As regards black money, it is known to the hon. member that Gavernment have appointed a high-power commission headed by Shri Wanchoo to go into this question. It is very difficult to ascertain what is the total amount of money, but it is not necessary that it should be only in the form of currency notes; it might be converted into other forms of property also.

CONSTRUCTION OF BIG BUNGALOWS FOR MINISTERS, HIGH COURT JUDGES AND SENIOR OFFICERS

+

1533. SHRI VALMIKI CHOUDHARY:
SHRI SURAJ BHAN:
SHRI SHARDA NAND:

Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided not to build big bungalows for Ministers, High Court Judges and senior officials;

(b) if so, the reasons for this decision;

(c) the maximum size of bungalows which will be constructed for the above categories in future;

(d) whether Government have drawn up any phased programmes to convert these big bungalows into small ones; and

(e) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY PLANNING; AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI K.K. SHAH) : (a) and (b). For ensuring the proper use of land and so as to achieve the population densities laid down in the Master Plan for Delhi, Government do not propose to construct big bungalows in future, save perhaps in a few exceptional cases.

(c) As the entire question of the redevelopment of large bungalow plots is still under consideration, it is too early to say whether small individual bungalows will be built at all or whether only flats will be constructed.

(d) and (e). As already stated, this question is under examination and no details can be given at present.

श्री वाल्मीकी चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं क्या यह फैसला समाजवादी समाज की स्थापना के उद्देश्य को ध्यान में रखकर लिया गया है ? यदि हां, तो भविष्य के लिए या वर्तमान के लिए भी है ?

दूसरा प्रश्न यह है कि तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए आवास की जो व्यवस्था की जाने वोली है, वह कब तक की जाएगी और कितने लोग उसमें अभी आते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वह सवाल तो अभी आने वाला है ।

श्री के० के० शाह : उसके लिए सेप्रेट सवाल है, तीसरी और चौथी श्रेणी के सिलसिले में । जो पहला प्रश्न उन्होंने पूछा उसके लिए मैंने कहा कि वह अन्डर कन्सीडेशन है ।

SHRI HEM BARUA: In view of the fact that there are big bungalows in big premises, may I know whether Government propose to utilise these big premises for constructing other bungalows there ?

SHRI K. K. SHAH : As I said, it is under consideration whether flats should be constructed or whether small bungalows should be constructed. I am taking into account the whole thing, what amount of surplus land can be released so that some funds can be generated which can be utilised for lower class of people.

SHRI N.K.P. SALVE : He has stated that barring exceptions big bungalows are not to be constructed. May I know which are those exceptions because the